take up certain housing schemes in the villages.

Secondly, these Ministers talk about rural housing and say that our country is marching towards socialism. But I know that even the Deputy Minister's bunglow has been provided with furniture, glass and windows at a cost of Rs. 45,000.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH): Rs. 22,000 in all, including all the electrical appliances, furniture, furnishing and everything.

SHRI DHIRESWAR KALITA: May be, it is 50 per cent of what I have said. The point is, we could have at least 20 houses at that Cost. Now, on the other hand, we are having palatial buildings. Mahatma Gandhi used to live in Sabarmati Ashram and the Sevagram in Wardha.

AN HON. MEMBER: Where are you living?

SHRI DHIRESWAR KALITA: I am living in whatever has been allotted to me by the Government. I do not want that we should all be provided with bunglows. What I want is that the attitude of the country should change. What is the present attitude? They are constructing five-storey buildings in Delhi and some other cities; they are not giving enough money for constructing houses in the villages, in the rural areas. You are having a revolving tower, making the Asoka Hotel an ideal hotel in the whole world. Ours is a very poor country. Today, in the morning, we passed a law for evicting unauthorised persons. We can evict those who are dwelling on the streets . . . .

AN HON. MEMBER: Not yet passed.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Well, I think it is going to be passed. They are going to give the Central Government the power to evict persons who are living in thatched houses or in hutments in unauthorised places. They will be evicted by the Government, but this Government does not take the responsibility for providing houses to the rural people, or those people who have not got any house at all. This is a shame and a sin for our country.

Thirdly, I wish to tell the mover of the resolution one thing. I know he belongs to the Swatantra Party. The private industrialists have been allotted some funds for the construction of houses to the coal-mines workers, industrial workers, etc. The money has also been allotted in their names. The hon. Member is not present here. He also belongs to the big industrial family. They are not providing houses to the industrial workers. Government also is not prepared to construct houses for workers. They are living in slum areas.

May I continue on the next day?

MR. CHAIRMAN: Yes. He may continue on the next day.

श्री ईश्वरराव पाटिल : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव के लिए टाइम और बढ़ाया जाय ।

सभापति महोदय : जब यह प्रस्ताव अगली बार इस सदन में आयगा और सदन आवश्यक समझेगा, तो इस का टाइम बढ़ा दिया जायेगा ।

17.31 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Demurrage paid by Food Corporation of India

श्री प्रेम शंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदया, इसी सत्र में मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 789 का उत्तर देते हुए माननीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों पर फूड कार्पोरेशन

[श्री वेणी शंकर शर्मा]

को प्राय: 1,43,412 रुपया डमरेज के रूप में देना पड़ा। हो सकता है कि अन्य स्टेशनों पर भी सरकार को डमरेज के रूप में कुछ रुपया और देना पड़ा हो।

मैं समझता हूं कि जिस मन्त्रालय का बजट 787 करोड़ रुपये के करीब है, उसमें 143 लाख रुपये का इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। किन्तु प्रश्न रुपये का नहीं है, यह रुपया तो सरकार के एक मन्त्रालय से दूसरे मन्त्रालय के पाकेट में जाता है वह घर के घर ही में रहता है उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं किन्तु इस प्रश्न के पीछे सरकार की जो अदूरदर्शिता और अकर्मण्यता है, उसी की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बजट सेशन के प्रारम्भ से यह बात साफ प्रकट हो गई थी कि इस बार देश में गेहूं की फसल बहुत अच्छी होने वाली है और उसके लिए सरकार ने पहले से लम्बी लम्बी स्कीमें बनानी भी शुरू कर दी थीं। इस छोटी सी पुस्तिका, "रीव्यू आफ़ दि फूड सिटुएशन इन इंडिया", में सरकार की ओर से कहा गया है :

"The phenomenal crop in Punjab, Haryana and UP has confronted the administration at the Centre and the States with the major problems of price support storage and movement."

खाद्य मन्त्रालय को उस समय से ही उचित प्रबन्ध करना चाहिए था और दूसरे मन्त्रालयों के साथ समन्वय और ताल-मेल स्थापित करना चाहिए था। किन्तु उसने वैसा नहीं किया। देश में गोदामों की आवश्यकता थी, लेकिन उनका समय पर निर्माण नहीं किया गया। खाद्य मन्त्रालय को रेल विभाग के साथ ताल-मेल स्थापित करना चाहिए था, लेकिन वह भी नहीं किया गया। फलस्वरूप हमने देखा कि वर्षा के कारण काफ़ी अन्न गल-सड़ गया और अनपेक्षित क्षति हुई।

कुछ ही दिन पहले माननीय मन्त्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि रेलवेज में तरपालों की कमी के कारण प्राय: 900 टन गेहूं खराब हो गया था, जो मनुष्य के खाने लायक नहीं रहा। प्रश्न केवल इसी बात का है कि आज हमारी सरकार के विभिन्न विभागों में आपस में समन्वय, सामंजस्य और ताल-मेल नहीं है। सभी मानो अपनी डफली और अपना अपना राग अलापते हैं, जिसका परिणाम हो रहा है हर जगह विशृंखलता, क्षति और अनपेक्षित व्यय।

एक ओर तो यह सरकार राइस मिलिंग इंडस्ट्री (एमेंडमेंट) बिल सरीखे कानून बनाती है। वह यह नहीं देखती कि उससे हमारे यहां कितनी बेकारी बढ़ेगी। गांवों में जो छोटे छोटे हल्लर्ज़ लगाये गये हैं, जिनसे लोगों की बेकारी की समस्या का काफ़ी समाधान हो रहा है, उनको सरकार बन्द कर रही है। पहले की जो मिलें चल रही हैं, उनको भी बन्द कर रही हैं। उसके बाद सरकार बड़ी-बड़ी मिलें स्थापित करना चाहती है, केवल इस लिए कि हमें पांच, छः, सात या आठ परसेंट अधिक अन्न उपलब्ध होगा। किन्तु हम भूल जाते है कि इस तरह हमारी सरकार कितना अन्न बर्बाद कर रही है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): Sharmaji did not agree on that day with the modern mills proposition.

SHRI BENI SHANKER SHARMA: Still I do not agree.

हमारी सरकार जो कुछ कर रही है, वह केवल एकाधिकार के अपने मोह के कारण, अपनी मानोपली की लोलुपता के कारण।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : अगर सरकार प्रक्योरमेंट न करती, तो किसान मर जाता।

श्री बेणी शंकर शर्मा : किसान जी जाता । मैं अभी बताता हूं कि कैसे ।

सरकार को अनाज खरीदने का सारा भार फूड कार्पोरेशन पर ही नहीं डाल देना चाहिये था । उसको अपने ऐजेंट खड़े करने चाहिये थे, जो अपने पैसे से अनाज उठा सकते । उसको प्राइवेट व्यापारियों को भी मौका देना चाहिये था कि अगर अनाज एक साथ मंडियों में आ जाये, तो वे भी उसको उठा लें ।

सरकार का कहना है कि हम क्या करें, इतना अनाज एक-साथ मण्डियों में आ गया कि हमारी सब स्कीमें फेल हो गईं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, स्टेशन पर माल ढोने के लिए कुली नहीं थे, रेलवे के पास डिब्बे नहीं थे, जिन स्थानों पर माल पहुंचता, वहां गोदाम नहीं थे । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह सब कुछ पहले देखना चाहिए था । आखिर सरकार किसे कहते हैं ? सरकार की एक प्लानिंग होती है, जिसके मुताबिक सब काम होता है । ऐसा न करके खाद्य मन्त्रालय ने बहुमूल्य अन्न का नुकसान किया । उसके लिए इस सरकार की जितनी भी भर्त्सना की जाये, वह थोड़ी है ।

आज इतना अन्न होते हुए भी सरकार फूड जोन्ज को न हटाने की अपनी जिद पर अड़ी हुई है । देश में अन्न की काफी पैदावार हुई है, जिसकी वजह से उसने कई जगह राशनिंग को भी ढीला कर दिया है । दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है । पश्चिमी बंगाल में सिलीगुड़ी के दक्षिण में, हैदराबाद और अन्य कई स्थानों में राशनिंग के साथ साथ खुले बाजार में भी अन्न मिल सके, ऐसी व्यवस्था की गई है । आज देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि दिल्ली की तरह हम हर जगह राशनिंग तो जरूर रखें, लेकिन उस के साथ साथ खुले बाजार में भी अन्न उपलब्ध करने की व्यवस्था कर सकते हैं । ऐसा न करने से आज क्या परिणाम हो रहा है ? श्री रणधीर सिंह ने कहा है कि किसानों को इससे बहुत नुकसान होता । लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब काफी अनाज मंडियों में आ गया और फूड कार्पोरेशन उस को नहीं उठा सका, तो उस वक्त किसान उस अनाज को अपने घर वापिस तो नहीं ले जा सकते थे, और न ही वे ले गये । तब मजबूर होकर उन्हें वह अनाज हृदयहीन एवं स्वार्थी व्यापारियों के हाथों कौड़ियों के मोल बेचना पड़ा ।

श्री रणधीर सिंह : सौ फीसदी ठीक कह रहे ह ।

श्री बेणीशंकर शर्मा : यह कहना गलत है कि सरकार की योजना से किसानों को बड़ा लाभ हुआ । सरकार को चाहिए था कि वह बाटम प्राइस निश्चित करके अपने साथ साथ प्राईवेट व्यापारियों को भी छोड़ देती । अगर वे दाम नीचे ले जाते, तो सरकार खुद उठा लेती । अगर वे उसी दाम पर माल उठाते तो उससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होता । अगर वे लोग ज्यादा दाम देकर माल उठाते, तो उससे किसानों को और लाभ होता । अगर एक हैल्दी काम्पीटीशन होता, तो किसानों को बहुत लाभ होता । और लोगों को भी अनाज सब जगह ठीक ढंग से मिलता । ऐसी अवस्था में मैं जो पहले कह रहा था आज समय आ गया है जब हमें फूड जोन को खत्म कर देना चाहिए ।

मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, कि उन्होंने मोटे अनाज से इस की शुरूआत की है । शायद गत मार्च से ही चने का मूवमेंट खोल दिया गया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि बिहार में जहां दो ढाई रुपये किलो चना मिलता था, बिहार के लोग आप जानते हैं, सत्तू खाने के बड़े शौकीन हैं, उन्हें अब चौदह पन्द्रह आने तक में चना मिल जाता है । वही अवस्था मक्के

[श्री वेणी शंकर शर्मा]

और जो की है । आज यह मोटा अनाज हर एक गृहस्थ को, हर एक किसान को, उसकी पाकेट के दामों के भीतर मिल जाता है । किन्तु जहां तक चावल और गेहूं का प्रश्न है वह अब भी उसकी पहुंच के बाहर है । एक तरफ तो हरियाना और पंजाब में अनाज सड़ रहा है, दूसरी ओर बंगाल और बिहार में हम उसके बिना भूखों मर रहे हैं । इसलिए मैं बड़े अदब से और बड़ी आजिजी के साथ मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह जितना शीघ्र हो सके फूड जोन सरीखो कृत्रिम व्यवस्था को हटावें । मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ प्रदेशों को मिला कर जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाना का एक विस्तृत क्षेत्र बनाया गया है और मैं समझता हूं कि जब उन्होंने यह एक्सपरीमेंट किया और उसमें उन्हें सफलता मिली है तो क्यों नहीं इस एक्सपरीमेंट को और आगे बढ़ाया जाय ? आखिर समूचा देश एक है । सब एक देश के वासी हैं अगर पूरा भोजन मिले तो सब को मिलना चाहिए, नहीं ना जो मिलता है उसी में आधा आधा बांट बांट कर के खा लेंगे ।

MR. CHAIRMAN: Shri Fernandes—He is not here. Shri Ramavatar Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : माननीय सभापति महोदया, मैं सवाल पूछने से पहले दो बातें कह देना अपना कर्तव्य समझता हूं । बिहार के विभिन्न स्थानों पर जो डैमरेज सरकार को देना पड़ा है या भारतीय खाद्य निगम को देना पड़ा है उसी की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए सवाल पूछना चाहता हूं । अभी 29 तारीख को भारतीय खाद्य निगम के मैनेजिंग डाइरेटर, श्री एन० पी० सेन पटना गए हुए थे और उन्होंने वहां एक प्रेस कान्फ्रेंस में यह बतलाया कि उनको किस तरीके से लाभ पहुंचना शुरू हो गया है । जो बातें उन्होंने कहीं, मैं उसको पढ़ करके सुना देना चाहता हूं :

"Mr. N. P. Sen, Managing Director, Food Corporation of India, disclosed here today that the FCI made a net profit of Rs. 3 crores in the financial year 1966-67 and paid 20 per cent bonus to 95 per cent of its staff, the maximum permitted under the Payment of Bonus Act."

दूसरी बात उन्होंने यह कही प्रेस कान्फ्रेंस में :

"The total value of foodgrains purchased by the FCI during this year was Rs. 250 crores out of which foodgrains worth Rs. 240 crores were sold."

वह आगे कहते हैं. . .

सभापति महोदया : माननीय सदस्य अब सवाल पूछें । कई और सदस्य सवाल करने वाले हैं और जवाब देने के लिए भी टाइम रहना चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : इससे रेलेवेन्ट है इसलिए पढ़ रहा हूं और इसी से सवाल निकाल कर पूछना चाहता हूं ।

"During the year 1967-68 the F.C.I. handled foodgrains of the value of Rs. 400 crores. The profits have not been calculated yet and the bonus would be declared only after the final accounting."

उन्होंने यह बतलाया कि तीन करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ । यह तीन करोड़ का मुनाफा तब हुआ जब अनाज की चोरी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, बरौनी में होती है, मुकामा में होती है, हमने खुद देखा, पटना में जहां आपका गोदाम है वहां कई दिनों तक ट्रेन के डिब्बे लगे रहते हैं और उसमें से लोग चोरी करके ले जाते हैं ।

श्री हा० मा० तिवारी (गोपालगंज) : तो अपने लोगों को समझाइये ।

श्री रामावतार शास्त्री : वह तो मैं समझाऊंगा लेकिन सरकार क्या कर रही है। यह मैं जानना चाहता हूं। मुझे खबर लगी है कि वहां का जो कन्ट्रैक्टर है वह उसी चोरी से लखपती हो गया . . . (व्यवधान) . . .

प्रेस वालों ने एक सवाल किया कि आप यह बताइये कि इतना नुकसान हुआ या फायदा हुआ, आपने कर्मचारियों को इतना बोनस दिया, आपको हर साल डैमरेज कितना देना पड़ता है ? इसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं इसी लिए पढ़ रहा था, उनको जवाब देना चाहिए था। अगर चोरी को बन्द कर दिया जाए और डैमरेज न देना पड़े तो जो बिहार में गेहूं का दाम बढ़ा दिया गया है वह बढ़ाने की नौबत नहीं आनी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास डैमरेज का स्टेट वाइज फीगर है कि एफ० सी० आई० को स्टेट वाइज कितना डैमरेज देना पड़ा है ताकि भारत की जनता को यह मालूम हो सके कि आप की लापरवाही की वजह से, आपके अफसरों की लापरवाही की वजह से जनता को कितना ज्यादा देना पड़ रहा है ?

श्री शिंकर (पंजिम) : सभापति महोदया, सवाल का जवाब मन्त्री जी की ओर से दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि जो डैमरेज भरना पड़ा वह डेमरेज कन्ट्रैक्टर ने भरा। इससे मालूम होता है कि उसकी रेस्पांसिबिलिटि कंट्रैक्टर के ऊपर थी। उसकी बेफिक्री से जो डेमरेज भरना पड़ा है वह तो वही भरत है लेकिन जो देर लगती है, ट्रान्सपोर्ट में जो देर लगती है उसकी वजह से वह देर में पहुंचता है। इसलिए मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा की वह जो कन्ट्रक्टर्स की लिस्ट है, उनको कन्ट्रैक्ट देने के समय कुछ ऐसी कन्डीशन्स फिक्स की जानी हैं या नहीं कि जो कन्ट्रैक्टर ऐसी बेफिक्री से या देर से डेमरेज भरने की परिस्थिति का निर्माण करते हैं जिससे नुकसान भी पहुंचता है तो उनको नए कन्ट्रैक्ट क्यों दिए जाते हैं और दिए जाते हैं तो वह और नुकसान करेंगे इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे जो कन्ट्रैक्टर्स हैं क्या उनके नाम लिस्ट से काटे जायेंगे ?

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं यह पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि डेमरेज अदा करने की जो नौबत आई उससे कम से कम इतना निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि भारतीय खाद्य निगम अदूरदर्शिता का शिकार हुआ है या उसकी लापरवाही के कारण यह स्थिति आई है या उसकी दक्षता में कमी के कारण यह स्थिति आई है। आज अपने देश के अन्दर जितनी फसल पैदा हुई उसका हम दुरुपयोग न करें और खास कर पंजाब और हरियाणा के अन्दर इसके पीछे मक्की का घोटाला हुआ था, उसको 6 महीने हो गए, उसके बाद भी स्टेशनों के ऊपर माल पड़ा सड़ता रहा और आज वर्षा ऋतु के अन्दर भी हरियाणा और पंजाब के अन्दर खुला माल अनेक स्टेशनों पर या अनेक स्थानों पर पड़ा है जिससे उसके खराब होने की सम्भावना है। क्या भारतीय खाद्य निगम और मन्त्री महोदय इस बात के ऊपर ध्यान देंगे कि परमात्मा ने जो हमारे ऊपर कृपा की वह हमारी लापरवाही और अदूरदर्शिता के कारण हम उसके अच्छे उपयोग का अवसर गंवा कर फिर से वैसी ही स्थिति का निर्माण न कर दें ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): I am thankful to the hon. members for having raised a few points which are discussed in the press and outside. This gives us an opportunity to explain our viewpoint. My humble submission is that much of the criticism which has been made on the floor of the House is misinformed and not based on correct assessment of the situation. May I submit that we should not forget the fact that, for the first time, in our country large marketable surpluses have emerged.

[Shri Annasahib Shinde]

It is really a thing of pride to all of us because all these years in the post-Independence period we were thinking how to increase agricultural production, and fortunately our efforts have succeeded. Our scientists have made contributions, our extension services have made contributions, and above all, the most important contribution has been made by the farmers. Now there is a feeling of confidence in the country that we can raise our production; we can make our country self-sufficient.

The other thing was this: if our food production increases and large surpluses emerge, will we be in a position to handle such marketable surpluses? May I submit for the information of this hon. House that, never in the past, in the agricultural history or in the history of market arrivals, have the market arrivals taken place on such an unprecedented scale; the wheat crop, especially, was so good in all parts of the country, especially in north India—Punjab, Haryana and U.P.—that the market arrivals from 15th May to 15th July were so enormous that I must say that they were beyond our expectations and beyond the assessment of the State Governments. This has thrown up some problems for us. But why should we take a pessimistic view of it? In fact, all along these years we were waiting for such a situation to develop and fortunately for us and happily for us a very favourable situation has developed in our country.

As I was submitting, large marketable surpluses have emerged and we wanted a public sector agency to take care of this. In this year the Food Corporation of India entered the market. In the beginning a number of people had apprehensions whether the Food Corporation of India would be in a position to handle the situation. But their doubts were misplaced and it was proved in practice that the strategy of the Government of India to put up a public sector agency like the Food Corporation of India in the market to face the situation was successful. The Food Corporation was in a position to purchase foodgrains worth roughly Rs. 135 crores in a period of seven to eight weeks. This is not a mean achievement.

Suppose the Food Corporation had not entered the field, what would have happened? Our experience in the past was that, whenever there were good crops, the prices got depressed and farmers suffered very severe losses, and then again production was adversely affected. But this time, a very important role was played by the Food Corporation of India; they were in a position to purchase almost all those marketable surpluses at a reasonable price, at the procurement price. This was the assurance which was given by the Government, by my Ministry, to the House and to the people. In Punjab especially this strategy proved hundred per cent successful.

Instead of looking to the very bright aspect of it, the hon. Member is trying to draw attention to various minor points. Even in regard to minor points, which the hon. Member has raised, I do not think he is very much justified. Some demurrage had to be incurred, but as is known the delivery of foodgrains, loading and unloading, is given to contractors and if the contractors do not load in time or do not unload in time, it is their liability. I will give certain figures in the case of, for instance, Punjab, Haryana, Delhi and Rajasthan. The figures are as follows: 1-1-1968—demurrage in the case of Punjab and Haryana Rs. 4,754. The U.P. figure is Rs. 1,364; the Delhi figure Rs. 1,37,000 (roughly); Bihar and West Bengal figures have not so far become available as the Railways have not yet submitted the bills. These are small figures. Even in regard to these, most of these amounts will have to be paid by the contractors to the F.C.I. because it was for them to unload the foodgrains in time.

SHRI BENI SHANKER SHARMA: I was not referring to the demurrage figures as such, but to the inactivity and lack of foresight on the part of the Corporation in this matter. I was not concerned with the petty amount involved.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: He has raised the discussion. I am explaining that according to the contract, it is the liability of the contractors to load or unload in time. I must go into details to find out the reason for this demurrage being incurred. This is a period of labour shortage everywhere; not only had the F.C.I. this experience, but even the Railways have had a similar experience. Because of this and a number of other factors which I can enumerate, this happened. For instance, rains also affected unloading; then due to use of open wagons also to a certain extent unloading and loading operations were delayed, because the wagons were of a different size, the normal loading operations naturally could not take place. Because of these, there was some amount of demurrage incurred. But it would be wrong to come to the conclusion that it was due to mismanagement or because we did not anticipate the situation.

Then the movements of foodgrains from Punjab and Haryana from 1st May to 17th July were on a big scale. Here are the figures. Market arrivals were 13,90,000 tonnes, procurement was 12,70,000 tonnes, movement was 7,07,000 tonnes. This is for Punjab. In the case of Haryana market arrivals were 2,92,000 tonnes, procurement was 2,03,000 tonnes and movement was 1,43,000 tonnes.

If we take into account the movement of imported foodgrains as well as those indigenously procured, about 21 lakh tonnes of foodgrains were moved in a period of 7-8 weeks. This was movement on an unprecedented scale. Here and there, some small things would have happened. I am prepared to look into it. In order to rectify the situation, we have appointed a committee under a very high official to go into any failure. If any failure has occurred, we shall try to fix responsibility on individuals. But by and large, my own impression and understanding is that the situation has been very well handled in the interest of the farmers and in the interest of the public. We have rich experience of this and we can now look forward to the future with confidence that the Corporation can handle the situation with confidence.

I know why the hon. Member has brought up this discussion. I can understand his viewpoint. He does not want the food zones. I know he does not accept the present arrangement. The trading community in India has some grievance against the zonal arrangements. I respect the views of the hon. member, but he should not try to bring in this agency for criticism on that score.

SHRI BENI SHANKER SHARMA: I do not belong to the trading community.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: He may not.

SHRI D. N. TIWARY: He may be a sympathiser.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: But some attempt is being made as if to show that the F.C.I. is not competent to handle the situation, that Government is not capable of dealing with the situation. Some sort of impression is sought to be created that there should be free trade in this country in this field. May I submit that if we have to solve our food problem satisfactorily in this country, a public sector agency like the Food Corporation must have a commanding position in the market. The Food Corporation of India is finding that position. I look forward to the future when it will get the commanding position not only in Punjab, Haryana and U.P. but all over the country. It will be good for the country, for the consumers and our farmers also. It is a public corporation and if it plays a vital and important role, the difficulties in the food

[Shri Annasahib Shinde]

front will be solved and we shall be in a position to have satisfactory marketing conditions.

18 hrs.

In regard to the other small points, I have nothing to say. As far as the point about demurrage is concerned—which was raised by Shri Shinkre and Shri Ramavatar Shastri—it has been replied in my earlier observations.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TWENTY-FIRST REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): I beg to present the twenty-first report of the Business Advisory Committee.

6.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 5, 1968/Sravana 14, 1890 (Saka).